खोरी में पुलिस की फर्जी सेवा... खुद ही थपथपा रहे अपनी पीठ

सोशल मीडिया पर वीडियो और टिप्पणियों के जरिए करा रहे हैं तारीफ

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: खोरी के परेशान हाल लोगों के बीच खाने के पैकेट और अन्य राहत सामग्री पहुंचाने का फरीदाबाद पुलिस ढोल पीट रही है। गोदी मीडिया एक खास वर्ग फरीदाबाद पुलिस के इस फर्जी अभियान में शामिल है। इतना ही नहीं फरीदाबाद पुलिस ने अपने चमचों के जरिए सोशल मीडिया पर भी वीडियो जारी कर और टिप्पणियां कराकर वाहवाही लूटने की कोशिश की है। खोरी में मीडिया के जाने पर गैरकानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। जो भी मीडियाकर्मी खोरी पहुंच रहे हैं वे या तो पुलिस के रहमोकरम से जा रहे हैं और सिर्फ पुलिस की बात छाप रहे हैं और कुछ मीडियाकर्मी वहां नाम और पहचान बदलकर गुप्त रूप से पहुंच रहे हैं।

खोरी को उजाड़े जाने की घोषणा होने पर पुलिस कमिश्नर के इस कथित निर्देश को बहुत जोरशोर से फैलाया गया कि फरीदाबाद पुलिस खोरी के लोगों को भूखा नहीं मरने देगी। वह उनके खाने का इंतजाम करेगी। लेकिन हकीकत क्या है...असलियत है कि पड़ोस के राधास्वामी सत्संग में खोरी के करीब 400 लोगों को भोजन दिया जा रहा है। यहां पर भूखे प्यासे पुलिस वालों को भी राधा स्वामी सत्संग से भोजन दिया जा रहा है। यहां पर करीब 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है लेकिन उनके खाने-पीने तक का इंतजाम फरीदाबाद पुलिस के अफसरों ने ठीक से नहीं किया। कई पुलिस वाले तो अब अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, मददगारों और घर वालों से खाना मंगाकर वहां खा रहे हैं।

कुछ एनजीओ ने भी यहां खाने के पैकेट पहुंचाने में मदद की है। जिनमें गुड फ्रेंड और गुड डीड एनजीओ शामिल हैं। चूंकि कोई भी एनजीओ बिना पुलिस अफसरों की मर्जी से खोरी वालों के बीच नहीं जा सकता है तो पुलिस अफसरों ने एनजीओ की सेवा में खुद का भी नाम शामिल कराकर सोशल मीडिया पर प्रचारित करा दिया। अब गुड फ्रेंड खाने के पैकेट बनाकर ला रहा है तो इसमें पुलिस की क्या भूमिका और क्या श्रेय है। पुलिस सिर्फ इतना करती है कि वह अपनी सुरक्षा में खाने के उन पैकेटों को एनजीओ से बंटवा देती है। इसी तरह गुड डीड एनजीओ ने खोरी वालों के बीच खाने-पीने की सूखी सामग्री के पैकेट बांटे। उसे भी पुलिस ने सुरक्षा दी लेकिन उसका भी श्रेय लेने की कोशिश फरीदाबाद पुलिस के अफसरों ने की।

फरीदाबाद पुलिस के अफसरों को फर्जी वाहवाही लूटने का चस्का लगा हुआ है। अभी पिछले हफ्ते एक बैंक गार्ड के शरीर का वजन ज्यादा होने पर फोटो लगाकर उसका मजाक उड़ाया गया था। इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने फरीदाबाद पुलिस का मजाक उड़ा डाला था। जिस अफसर ने इस ट्वीट को किया था, उसने रेत में अपना मुंह छिपा लिया है। इस संबंध में डीजीपी हरियाणा के पास भी लोगों ने शिकायत की है कि हरियाणा पुलिस के अधिकारी मोटापे पर पहले अपने गिरेबान में झांके तब मामूली वेतन पाने वाले गार्ड का मजाक उड़ाएं। डीजीपी हरियाणा से कहा गया कि ऐसे पुलिस अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जो इस तरह के घटिया ट्वीट कर रहा है। इसी तरह एक गाय के गड्ढे में गिरने और पुलिस द्वारा उसे बचाने की खबर का प्रचार भी फरीदाबाद पुलिस ने खूब जोरशोर से किया लेकिन जिस वजह से वह गाय उस गड्ढे में गिरी, उस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस कमिश्नर के घर के आसपास पानी भरा हुआ है। उस पानी को हटवाने या नगर निगम पर कार्रवाई की बजाय सभी ने चुप्पी साधी हुई है। इसका नतीजा यह निकल रहा है कि सारे फरियादी या परेशान लोग पुलिस कमिश्नर के कैंप कार्यालय पर अपनी शिकायत लेकर कम पहुंच पा रहे हैं। यह बारिश जनता से दूरी बनाने में पुलिस की ढाल बन गई है।

पेगासस पर सुनवाई को राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट, क्या सच सामने आएगा?

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

नई दिल्ली: पेगासस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो काम के हिसाब से अगले हफ्ते केस को लिस्ट कर सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वो भारत सरकार के जिम्मेदार लोगों को इस मामले में तलब कर सकेगा। पेगासस जैसे जासूस उपकरण लेने का फैसला गृह मंत्रालय या किसी अन्य मंत्रालय के बाबू ने नहीं किया होगा। इसकी खरीद निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय के जरिए उच्चस्तर पर बातचीत के बाद की गई होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी हिम्मत दिखा पाएगा। यह नामुमकिन है कि इसकी आंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच पाएगी। इस बीच विपक्ष ने भी शुक्रवार को इस पर अपनी रणनीति बनाई। उसकी रणनीति का असर संसद में दिखेगा।

सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने पेगासस मामले को मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के संज्ञान में रखा। सिब्बल ने वरिष्ठ पत्रकार एन. राम की याचिका को चीफ जस्टिस के समक्ष मेंशन किया और जल्द सुनवाई की मांग की. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वो अगले हफ्ते मामले की सुनवाई करेंगे लेकिन वर्क लोड भी देखना होगा। इस बीच पेगासस बनाने वाली इस्राइली कंपनी एनएसओ ने पूरी दुनिया में जिन देशों को इसे बेचा था, उन्हें इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। हालांकि वो देश अपने विरोधियों की सारी बातों के सबूत, उनकी गतिविधियां आदि अपने पास सुरक्षित रख चुके हैं। ऐसे में एनएसओ की इस रोक का कोई फायदा नहीं होगा।

ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल का सत्यानाश करने का जिम्मा आरडी को

फ़रीदाबाद (म.मो.) हज़ारों करोड़ की लागत से एनएच तीन में बना ईएसआई का मेडिकल कॉलेज अस्पताल जिसमें रोज़ाना करीब 4000 मरीज़ ओपीडी में आते हैं तथा 500-600 मरीज़ भर्ती रहते हैं। करीब 30 एकड़ में फ़ैले इसके परिसर की देख-भाल का दायित्व ईएसआई कार्पोरेशन ने आरडी (क्षेत्रीय निदेशक) को सौंप रखा है। इनका पंचतारा सुविधाओं से सुसज्जित कार्यालय सेक्टर 16 में स्थित है। इसलिये इन्हें इस बात से कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अस्पताल का एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट)चल रहा है या नहीं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अस्पताल का सीवेज मैनहोल से ओवर फ्लो होकर परिसर में बह रहा है।

अस्पताल एवं छात्रावासों में कब पानी की सप्लाई बंद हो जाय कोई नहीं जानता। लैंड स्केपिंग यानी खाली ज़मीन में घास एवं पेड़-पौधों की देख-रेख करने को पर्याप्त माली इत्यादि हो न हो इन्हें कोई लेना-देना नहीं। घास और पौधे सूख रहे हैं तो उनकी बला से। किसी छत पर 8-8 इन्च बरसाती पानी खड़ा होकर लेंटर को गला रहा है तो गलता रहे। माल यानी जायदाद सरकारी है, उनके घर से क्या जाता है ? दिनांक 30 जुलाई को जब यह संवाददाता इस अस्पताल की कैजुअल्टी की ओर जा रहा था तो देखा कि सीवर का काला एवं बदबूदार पानी, जो फ़िलहाल तो लॉन में भरता जा रहा था और शीघ्र ही सड़क पर भी फ़ैलने वाला है। इसी के दूसरी तरफ़ यानी डीन ऑफ़िस से कैजुअल्टी की ओर जाने वाले रास्ते के बाईं ओर बेसमेंट की छत पर 8-8 इन्च पानी खड़ा है, जिसके निकास का कोई रास्ता नहीं। और तो और इसी रास्ते की छत भी टपक रही है, जाहिर है उसके ऊपर भी बरसाती पानी खड़ा है। यह दुर्दशा तो उन स्थानों की है जो बिना ध्यान दिये भी आने-जाने वालों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, उन जगहों की क्या हालत होगी जिन पर बिन ध्यान दिये नज़र नहीं पड़ती। विदित है कि सेक्टर सात की ईएसआई डिस्पेंसरी मात्र 40 साल में ऐसी ही लापरवाही की बलि चढ़ चुकी है।

इस दुर्व्यवस्था बाबत पूछताछ करने पर जानकारों ने बताया कि जिस निकृष्ट सरकारी बिल्डर यूपी सेतु निगम को इस अस्पताल भवन निर्माण का ठेका दिया गया था उसी चोर को इसके रख रखाव का भी ठेका दे दिया गया है। इस चोर ने अपना कमीशन काट कर आगे किसी छोटे-चोर को ठेका दे दिया और उसने सबसे छोटे चोर जगदम्बा नामक किसी कम्पनी को इस परिसर का सत्यानाश करने का ठेका दे दिया है।

जानकार बताते हैं कि इन्ही चोर कम्पनियों ने ही वे नाकारा एसटीपी लगाये हैं जो आज पूरी तरह से ठप्प पड़े हैं। सीवर का कोई कनेक्शन एमसीएफ़ से लिया नहीं गया हे लिहाज़ा ठेकेदार ने चोरी से सड़ा हुआ सीवेज डीएवी कॉलेज की ओर निकालना शुरू कर दिया था; लेकिन जब डीएवी वालों ने उसका वीडियो बना कर कार्यवाही करने की धमकी दी तो इन्होंने कुछ सीवेज पुरानी बिल्डिंग वाले मेनहोल के जरिये तथा कुछ, एक अन्य भूमिगत पाइप के जरिये एमसीएफ़ के सीवर में डालना शुरू कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीन एवं चिकित्सा अधीक्षक के पल्ले इस मामले में कुछ नहीं, ये केवल आरडी के साथ-साथ समय-समय पर मुख्यालय को पत्र लिखते रहते हैं, जिन्हें शायद कोई पढना भी गवारा नहीं करता।

अब युवकों में ऑनलाइन जुए की लत लगाने का गेम

नैतिकता और पत्रकारिता ताक पर रख अख़बार छाप रहे विज्ञापन

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद : बहुत शातिराना तरीके से बच्चों में पहले ऑनलाइन गेमिंग की लत लगाई गई और अब अपना असली उद्देश्य यह गेमिंग इंडस्ट्री सामने लाई है यह है ऑनलाइन जुआ।

आज दैनिक भास्कर अख़बार में पहले पेज पर फुल पेज विज्ञापन छपा है कि 'स्पिनर घुमाओ ओर विनर बनो'... कल तक यह कम्पनियां ढके छुपे ढंग से भारत में ऑनलाइन रम्मी ओर आईपीएल क्रिकेट टीम बनाने के खेल खिला रही थीं लेकिन आज तो पानी सर से गुजर गया है। आज तो साफ साफ कैसिनो की स्पिनर मशीन का ही फोटो लगा कर कहा जा रहा है कि इसे घुमा कर दांव लगाइये ओर जीत लीजिए आईफोन 12 जैसे प्राइज ! यह सरासर जुआ है।

गेमिंग का शौक अधिकतर बच्चों ओर युवाओं को होता है और वह गेम खेलने वक्त अपना भला-बुरा नहीं समझ पाते। भारत में 53 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हैं। अधिकतर स्मार्टफोन इन्ही के पास है। यही इन ऑनलाइन गेमिंग कम्पनियो के टारगेट है, आपने देखा ही होगा कि आईपीएल के साथ जमकर ऑनलाइन जूए से सम्बंधित गेम्स को प्रमोट किया गया था।

पत्रकार गिरीश मालवीय कहते हैं - खुद ऐसे लोगो को जानता हूँ जिन्हें पिछले

लॉकडाउन में ऑनलाइन गेम खेलने का नशा चढ़ गया। उन्हें लगा कि गेम खेलकर बहुत सारा पैसा आसानी से कमाया जा सकता है और इसी कोशिश में वो बहुत सारा पैसा गवां बैठे। आज वो लोग आर्थिक मुश्किलों में घिरे हुए हैं। भास्कर में जिस कम्पनी का यह विज्ञापन है उसके पास अभी 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर हैं और "2022 के अंत तक 2 करोड़ 50 लाख यूजर तक पहुंचने का लक्ष्य बनाए हुए है"।

इस तरह के विज्ञापन के जरिए वह अपने ब्रांड की आक्रामक ब्रांडिंग कर रहे हैं। तीन हफ्ते पहले ही उसे अमेरिकी कम्पनी ग्रिफिन गेमिंग पार्टनर्स से 65 मिलियन डॉलर का निवेश मिला है। साफ दिख रहा है कि खुलेआम ऐसे विज्ञापनों के जरिए ऑनलाइन जुए का जहर युवाओं में फैलाया जा रहा रहा है एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा और तमाम सरकारें चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार सब कुछ देखते हुए भी चुप होकर बैठी हुई हैं।

ऐसे में जब दैनिक भास्कर पर आयकर विभाग के छापे पड़ते हैं तो पत्रकारिता की नैतिकता की दुहाई दी जाती है। इसी तरह टाइम्स आफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स समेत तमाम अख़बार कॉल गर्ल्स उपलब्ध होने के विज्ञापन एस्कोर्ट सर्विस मुहैया कराने के नाम पर छाप रहे हैं। यही वजह है कि मज़दूर मोर्चा विज्ञापन के सहारे चलने वाला अख़बार नहीं है, यह जनता के चंदे और सहयोग से चलाया जा रहा है। मज़दूर मोर्चा में विज्ञापन छापने से पहले यह देखा जाता है कि कहीं ग़लत मक़सद से तो विज्ञापन नहीं छपवाया जा रहा है?